अफ्रीका के क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों के साथ भारत की भागीदारी

डॉ. संदीपनी दास *

भारत ने अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ परम्परागत द्विपक्षीय संपर्कों के माध्यम से और महाद्वीपीय स्तर पर अफ्रीकी संघ (एयू) के माध्यम से बहुपक्षीय संपर्क कायम करके और क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़) से संपर्क करके अफ्रीका के साथ एक त्रिस्तरीय सहयोग विकसित किया है। एक विकास-भागीदार के रूप में भारत ने क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में अफ्रीकी नेतृत्वों द्वारा प्रदान किए गए महत्व को पहचाना है, जिसके परिणामस्वरूप इस महाद्वीप के साथ अपने वर्तमान संपर्क में नई दिल्ली का विशेष ध्यान क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़) पर गया है।

अफ्रीका में 40 से अधिक क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय (आरईसी) हैं और अफ्रीकी संघ (एयू) ने इनमें से आठ को मान्यता दी है। इन प्रमुख क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़) में शामिल हैं: मध्य अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय (ईसीसीएएस), अन्तर-सरकारी विकास प्राधिकरण (आईजीएडी), पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (ईएसी), पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय (ईकोवास), पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार (कोमेसा), दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी), सहेलो-सहारा राष्ट्र समुदाय (सीईएन-एसएडी) और अरब पश्चिम संघ (यूएमए)।

विगत दशकों में, इन समूहों ने मानकों और नियमों के सामंजस्य के साथ साथ साझा बाजारों के निर्माण की ओर कदम बढ़ाए हैं। ये बहुपक्षीय संस्थाएं विशेषकर कृषि, खनन और तेल एवं गैस के क्षेत्र में प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास के साथ-साथ बेहतर बुनियादी ढ़ांचे तथा क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से वस्तुओं तथा सेवाओं के बेहतर आवागमन की दिशा में कार्यरत रही हैं। क्षेत्रीय एकीकरण की इस प्रक्रिया का अफ्रीकी देशों के साथ भारत

के व्यापार एवं निवेश संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अफ्रीकी क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़) ने भारत के निजी क्षेत्र के साथ संपर्क कायम करने की उत्सुकता दिखलाई है ताकि वे इन्हें बड़े व्यापार तथा निवेश अवसरों के लिए आकर्षित कर सकें। इन क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़) ने भी क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि के क्षेत्र में अफ्रीका की अपेक्षाओं के प्रति भारतीय एजेंसियों को सु ग्राही बनाने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

अफ्रीकी संघ (एयू) द्वारा मान्यताप्राप्त ये आठ क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़), जुलाई, 2006 में गाम्बिया की राजधानी बांजुल में संपन्न भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) में लिए गए निर्णय के आधार पर भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) के अभिन्न अंग हैं। बांजुल फार्मूले के अनुसार, इन आठ क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़) के अध्यक्ष देशों को अप्रैल, 2008 में नई दिल्ली में संपन्न प्रथम भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) में आमंत्रित किया गया था। क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग सहित भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच त्रिस्तरीय संपर्क की पहचान भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) प्रक्रिया के तहत की गई थी। प्रथम शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) की कार्य-योजना में क्षेत्रीय पर आबंटित विकास सहायता के कतिपय घटक (शामिल) थे। द्वितीय शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) की कार्य योजना, जिसकी शुरूआत 6 सितंबर, 2013 को हुई, में अनेक क्षेत्रीय पहल भी किए गए थे। भारत ने 32 क्षेत्रीय संस्थाएं स्थापित करने का सुझाव दिया है, जिनकी अवस्थिति पर निर्णय क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़) के परामर्श से लिए गए हैं। इसके अलावा, नई दिल्ली ने इथियोपिया- जिबुती रेल लाईन के लिए 30 करोड़ अमरीकी डॉलर मूल्य की ऋण श्रृंखला (एलओसी) प्रदान करके क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के अफ्रीकी संघ (एयू) के प्रयासों का समर्थन किया है।

अफ्रीकी क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़) के साथ अपने संपर्क को पुनर्जीवित करने के प्रयास में, नई दिल्ली ने अब तक पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (ईएसी), पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार (कोमेसा), पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय (इकोवास), दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी) और अंतर-सरकारी विकास प्राधिकरण (आईजीएडी) के साथ समझौता ज्ञापन (समझौता ज्ञापनों) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत अधिकारी/मंत्री स्तरों पर विचार विमर्श होते रहते हैं। इसके अलावा, मध्य अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय (ईसीसीएएस) के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है। अफ्रीकी आर्थिक जगत में अंतर-क्षेत्रीय संपर्क करने के हाल के रूझान के बाद से इन क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़) के साथ नई दिल्ली के संपर्क और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के

वर्ष 2015 में पूरा होने की संभावना है। त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार करार, जिसके लिए दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी), पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार (कोमेसा) और पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (ईएसी) के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है, से 26 अफ्रीकी देशों में रह रहे 60 करोड़ लोगों अथवा अफ्रीकी संघ (एयू) के सदस्य देशों में से आधे को लगभग 1 अरब अमरीकी डॉलर के संयुक्त घरेलू उत्पाद से लाभ होने का अनुमान है।

14-16 नवंबर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित प्रथम भारत-अफ्रीकी क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़) की बैठक के साथ ही अफ्रीका के क्षेत्रीय समूहों के साथ भारत की संलग्नता एक निर्णायक स्तर तक पहुँच गई। जहां भारत के इससे पहले कुछ अफ्रीकी क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़) के साथ संपर्क थे और इसने उनमें से चार (देशों) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, परन्तु इस अवसर पर सभी सदस्य देशों के साथ एक ही मंच पर संपर्क करने की पहल की गई थी। ऐसे संस्थागत संपर्क से सहयोग की रूपरेखा और कार्यान्वयन प्रक्रियाएं तैयार करने हेतु अधिकाधिक अवसर प्राप्त हुए हैं। पहली भारत-अफ़्रीकी क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़) की बैठक में पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार (कोमेसा) और पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (ईएसी) के महासचिवों, पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय (इकोवास) के अध्यक्षों, दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी) के उप कार्यकारी सचिव, सहेलो-सहारा राष्ट्र समुदाय (सीईएन-एसएडी) के राजनीतिक मामलों के प्रभारी सलाहकार, अरब पश्चिमी संघ (यूएमए) के राजनीतिक मामलों के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था।

द्वितीय भारत-अफ्रीकी क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़) की बैठक 8-9 नवम्बर, 2011 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक में पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार (कोमेसा), पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (ईएसी) तथा मध्य अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय (ईसीसीएएस) के महासचिवों, अन्तर-सरकारी विकास प्राधिकरण (आईजीएडी) के कार्यकारी सचिव और दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी) तथा पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय (इकोवास) के प्रतिनिधियों के साथ-साथ उनके प्रतिनिधिमंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़) के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से सहमत कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कार्यरत/संलग्न भारत सरकार के अनेक विभागों/मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ बैठक की। क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़) के प्रतिनिधिमंडलों ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा का दौरा किया और विश्व मामलों की भारतीय परिषद, सप्रू हाउस द्वारा आयोजित एक शैक्षणिक संवाद में भी भाग लिया। 8 नवंबर 2011 को भारत और अन्तर-सरकारी विकास प्राधिकरण (आईजीएडी) के बीच आर्थिक सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों

और अफ्रीकी संघ (एयू) के साथ संयुक्त कार्य योजना के माध्यम से लिए गए सभी निर्णयों सहित उपयुक्त कार्य योजनाओं पर मिलकर कार्य किया जाएगा।

तीसरी भारत-अफ्रीकी क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़) की बैठक 20-21 अगस्त, 2014 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक में पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (ईएसी) के महासचिव, अन्तर-सरकारी विकास प्राधिकरण (आईजीएडी) के कार्यकारी सचिव, सहेलो-सहारा राष्ट्रीय समुदाय (सीईएन-एसएडी) के कार्यवाहक महासचिव, पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार (कोमेसा) के सहायक महासचिव तथा मध्य अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय (ईसीसीएएस) के निदेशक ने भाग लिया था। क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़) के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत के विदेश राज्य मंत्री, जनरल डॉ. वी के सिंह (सेवानिवृत्त) के साथ 20 अगस्त, 2014 को मुलाकात की। उन्होंने कुछ सिविल सोसायटी संगठनों, व्यापार संगठनों, शिक्षा संस्थाओं और थिंक टैंक, जैसे कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग; बेयरफूट कॉलेज, तिलोनिया; ऊर्जा तथा संसाधन संस्थान; भारतीय उद्योग परिसंघ; भारतीय दूरसंचार परामर्श लिमिटेड के साथ-साथ भारत सरकार के अनेक विभागों/मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ वार्ताएं कीं। क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़) के प्रतिनिधियों ने विश्व मामलों की भारतीय परिषद, सप्रू हाउस द्वारा आयोजित एक शैक्षणिक संवाद में भी भाग लिया। यह बैठक अपार महत्व रखता है, क्योंकि भारत 4 दिसंबर, 2014 को भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) के महत्वपूर्ण तीसरे दौर की मेजबानी करने जा रहा है।

भारत-अफ्रीकी क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (आरईसीज़) की बैठक प्रक्रियाओं से नई दिल्ली को अफ्रीका नीति के संबंध में जानकारियां उपलब्ध हुई हैं और इसने प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और ऋण श्रृंखलाओं के रूप में की गई पहलों को सुव्यवस्थित किया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनुमान लगाया गया है कि भारत विभिन्न हितधारकों से राय ले रहा है और अपनी पहल को उनकी प्राथमिकताओं और वरीयताओं के अनुसार ढ़ाल रहा है। इससे राजनीतिक, आर्थिक और इससे संबंधित डोमेन/अनुक्षेत्र में भारत-अफ्रीकी सहक्रिया का सृजन हुआ है। अफ्रीका में अंतर-क्षेत्रीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढ़ांचे और क्षमता निर्माण परियोजनाओं में मजबूत भागीदारी बनाने की आवश्यकता है।

** डॉ. संदीपनी दास विश्व मामलों की भारतीय परिषद, सप्रू हाउस, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।*